आतंकवाद और चीन का वीटो

अविनाश गोडबोले, Mar 15 2019

यह बिलकुल अपेक्षित ही था, एक बार फिर से चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) के प्रस्ताव 1267 के तहत मसूद अजहर को प्रतिबंधित सूत्री में डालने पर वीटो लगाया है। हाल के दिनों में 'तकनीकी रोक' लगाने वाला यह चीन का चौथा वीटो है। अपने इस कदम से चीन ने भारत को यह बताया है कि आतंकवाद भारत की अपनी राष्ट्रीय समस्या है।

साथ ही उसने यह भी जता दिया है कि 'वैश्विक आतंकवाद' और उसकी दक्षिण पश्चिम की नीतियाँ में अंतर स्क्रैपल है। यहाँ तक कि 41 जानें लेनेवाला आतंकी हमला भी चीन के नजरियों में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। भारतीय चिंताओं को लेकर उसके प्रयोक्ताओं में कोई बदलाव नहीं आया है।

इससे यह संदेश स्पष्ट है कि पाकिस्तान के साथ चीनी संबंध समृद्ध रहे जा गए और शहद से भी मीठा है। यहाँ तक कि उभरती जिम्मेदार शक्ति के तौर पर प्रतिष्ठा से ज्यादा उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा अधिक मायने रखते हैं। कुल मिलाकर चीन एक स्वार्थी उभरती शक्ति रूप में अपनी पहचान बना चुका है।

लंबे समय से भारत इस बात को जानता है कि 'वैश्विक आतंकवाद' जैसी कोई चीज ही नहीं है। अमेरिका ने 9/11 के बाद अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच लाइन खींचने के लिए इस मुहावरे को गढ़ा था। एक बड़े विकासशील देश के तौर पर भारत को एक पक्ष लेना था। हालांकि, वैश्विक आतंक पर हमले के नाम पर जब अमेरिका अपने वास्तविक और कानूनी कुछ जरूरतों पर अफगानिस्तान और फिर इराक में कहर बरपा रहा था, तब भारत उसके समर्थन में खड़ा था।

इसी दौरान अमेरिका ने सबसे महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी के तौर पर पाकिस्तान की खोज की थी। अपनी राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की नीतियों से पाकिस्तान जब भारत में आतंकवाद को जारी रखे हुए थे, तब अमेरिका उसे नजरअंदाज करता रहा। इस दौरान पाकिस्तान नकदी व सामान के रूप में सहायता प्रदान करता रहा। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों भारत के खिलाफ हवाई हमले में पाकिस्तान ने अमेरिकी एफ-16 विमान का इस्तेमाल भी किया।
इस बार चीन है और आर्थिक मदद के रूप में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) प्रोजेक्ट है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना है। चीन का 62 बिलियन डॉलर का योजना पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य को नहीं बदल सकता, लेकिन यह उसके स्व-उद्देश्य के लिए एक बड़ी वजह है।

सीपीईसी पाकिस्तान की उस क्षमता का उदाहरण है, जिसके माध्यम से वह ग्राहक राज्य (क्लाइंट रूप) बनकर महान या प्रमुख शक्ति के हितों की पूर्ति कर रहा है। चीन के लिए सीपीईसी वह नजदीक है, जिसके माध्यम से वह न सिर्फ़ पाकिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान, हिंद महासागर, ईरान और खूद के झिंगियांग प्रांत में अपने हितों को एक साथ साथ रहा है। जानिए, चीन एक साथ अपने कई हितों को साथनेवाले देश का साथ आखिर क्यों छोड़ता है?

भारत किस चीज़ की पेशकश कर सकता है, जो पाकिस्तान की भूमिका के मुकाबले चीन को ज्यादा आर्थिक लगे, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली में कई लोग ऐसा मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विदेशी कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) में उपाधिक्षर के लिए भारत द्वारा चीन का समर्थन उसकी सोच में बदलाव ला सकता है। हालांकि, स्पष्ट तौर पर यह मुद्दा नहीं है।

चीन को भारत से जिस सीदे की आस है। वह संभवतः यह है कि भारत बीआरआई में शामिल होने का इरादा कर ले। यद्यपि, कई आधारों पर बीआरआई के विरोध में ध्वजवाहक की अपनी स्थिति के बारे में भारत को गहराई से पता है, जो श्रीलंका, मलेशिया, युगांडा और एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों की स्थिति को देखते हुए बारंबार सही प्रतीत होता है। ऐसे में इस आधार पर किसी वादी की उम्मीद करना बेकार है।

गौरतलब है कि चीन के झिंगियांग प्रांत में बीते पांच वर्षों में आतंकवाद संबंधी ज्यादातर घटनाएं दक्षिणी झिंगियांग में ही घटी हैं, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है।

चीन जानता है कि पाकिस्तान ही इन आतंकी घटनाओं का स्रोत है, फिर भी वह पाकिस्तान का रक्षा कवच बना हुआ है। यह कहा जाता है कि पाकिस्तान खूद आतंकवाद से परेशान देश है और इसके लिए वह खूद ही जिम्मेदार भी है। अब इस वीटी के बाद इस तरह के दोतरफा आतंकवाद विरोधी अभ्यासों की रोकना ही तरकबंगत कदम होना चाहिए। अब यह स्पष्ट है कि भारत और चीन में द्विपक्षीय संबंध सामान्यतः कमजोर है।

अब प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थित में भारत का विकल्प क्या होगा? यहां यथार्थवादी हत्याकांड से यह तर्क दिया जा सकता है कि एक बार फिर वीटी करने की चीन की नीति जैसे-ए-मोहम्मद के बालाकोट शिविर पर भारत द्वारा किये गये एहतियात हमलों को न्यायिक ठहराता है। भारतीय हत्याकांड से, वैश्विक प्रणाली आज की तारीख में अराजकता का
प्रतिनिधित्व करती है. किसी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने या प्रतिबंधित करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया टूट चुकी है.

यह प्रमुख शक्तियों के हितों की संरक्षक भर है. भारत संयुक्त राष्ट्र से जो अपेक्षा करता है, उसे स्वयं करना होगा. सीमा पार से जिस आतंकवाद की समस्या का वह सामना करता है, उसे खत्म करने के लिए वह जो उपाय कर रहा है, वह सही है, लेकिन इसे लेकर भारत को व्यावहारिक होना होगा. भारत की बदले की प्रतिक्रिया, भारत के लिए उपलब्ध विकल्पों का नतीजा है.

दूसरे स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अपने राष्ट्रीय उद्देश्य हेतु शामिल होने के लिए भारत के अथक प्रयास से भी यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत दक्षिण एशिया में चीन की शक्ति को एक महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में मान्यता देता है. अगर ऐसा है, तो इसे आगे बीजिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय उपायों के जरिये अपने तरीके से काम करना होगा.

वहीं दूसरी ओर, अगर भारत का इरादा केवल इस आधार पर चीन को घेरना है कि वह 'एक जिम्मेदार उभरती शक्ति' की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो वह भी पर्याप्त नहीं है. चीन कभी भी पाकिस्तान के सामने असहज नहीं होने जा रहा है. भारत की अराजकता को पहचानने और खुद के बूते अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने की जरूरत है.